IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

जनजातियों और पर्यावरण संरक्षण

Virendra Kumar Jhariya
Assistant Professor, Department of ART
Mekalsuta College, Dindori

सारांश: सबसे पहले, आदिवासी कौन हैं और वन का गठन क्या है, इस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा, सामाजिक-आर्थिक और कानूनी पहलुओं में आदिवासियों और जंगल के बीच मौजूद संबंधों को इंगित किया गया है। यह यह भी स्थापित करता है कि इस तरह के संबंध का एक मजबूत कानूनी आधार है, हालांकि यह मुख्य रूप से सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं और परंपराओं पर स्थापित है।

दूसरे, कागज परंपराओं और प्रथागत कानूनों के मिश्रण के साथ मौजूदा विभिन्न कानूनों से संबंधित है। इसमें वनों की रक्षा के लिए कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है। वन अधिनियम का उद्देश्य इस अर्थ में देखा जाता है जैसे कि अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता पूर्व के दौरान शोषण तंत्रों में से एक था। इस खंड में आदिवासियों के साथ अन्य परस्पर विरोधी कानूनों को उजागर करने वाले उपयुक्त कानूनों के लिए विचारों की कमी की भी शिकायत की गई है।

तीसरे, आदिवासियों और उनकी भूमि पर शासन करने में विभिन्न बाधाओं का सामना किया जा रहा है, जिसमें संवैधानिक सुरक्षा उपायों को चूने के प्रकाश में लाया गया है। यह विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और कानूनी कठिनाइयों और इन कानूनों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान सामना किए गए विभिन्न अवरोधों के स्वाद के साथ कमियां भी बताता है। अंत में, कागज एक समस्या को हल करने वाले मॉडल के साथ समाप्त होता है, जो लेखकों द्वारा लाया जाता है जिसमें कल्याणकारी राज्य होने के नाते, आदिवासियों के विकास और विस्थापन के बीच रेखा खींचने के लिए सुझाव और सिफारिशें हैं, सर्वोपरि महत्व लोगों का कल्याण है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य के आर्थिक हित के साथ-साथ आदिवासियों के अस्तित्व के लिए एक मॉडल का निर्माण करने के अपने कई निर्णयों में कई निर्णय शामिल हैं।

प्रस्तावना:-

भारत में वनों के प्रति अपने स्वयं के आरक्षण हैं और उन्होंने प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया है। प्राचीन भारतीय शास्त्र जैसे महाभारत और रामायण दंडकारण्य और

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

नंदवाना में वन जीवन के सुरम्य वर्णन करते हैं। मुगल सम्राट थे जिन्होंने ऑर्किड बनाने को प्रोत्साहित किया, जिन्हें ha भावों 'के नाम से जाना जाता था और दूसरी ओर अशोक और शिवाजी जैसे राजाओं ने आदेश जारी किए कि वे सड़कों के किनारे और कैंपिंग स्थलों पर पेड़ों के रोपण को प्रोत्साहित करें और फलों के पेड़ों की कटाई पर रोक लगाएं। सामान्य तौर पर, भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले, जंगल के लोगों के उपयोग का विनियमन मुख्य रूप से स्थानीय रीति-रिवाजों और कानूनों के माध्यम से किया गया था। ये बरगद जैसे पेड़ काटने को हतोत्साहित करते हैं और इसलिए समाज के साथ इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक संघों को देखते हैं। कई मंदिरों में वनों को पवित्र माना जाता था और पेड़ों को काटने की मनाही थी। अब भी हमारे पास देश में कुछ देवराय हैं ।1

अफ्रीकी महाद्वीप के बाद भारत में जनजातीय आबादी का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 6.78 करोड़ है, जो देश की 83.86 करोड़ की कुल आबादी का लगभग 8.08% है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य की जनसंख्या को छोड़कर जहाँ जनगणना नहीं की जाएगी। अशांत स्थिति। इसमें से लगभग 87 फीसदी अनुसूचित जनजाति की आबादी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को कवर करने वाली केंद्रीय बेल्ट में केंद्रित है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लगभग 10 प्रतिशत और अन्य राज्यों में लगभग 3 प्रतिशत हैं। मध्य प्रदेश में देश में 1.54 करोड़ अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे अधिक है। 2

आदिवासी आबादी के पिछड़ेपन के मुख्य कारण शोषण और अशिक्षा हैं। आदिवासियों को लगातार गर्त में शराब और पैसे उधार दिए जा रहे हैं। शोषण के खिलाफ प्रभावी संरक्षण और साक्षरता में सुधार के बिना आदिवासियों का आर्थिक विकास संभव नहीं है। स्थिति की सावधानीपूर्वक समीक्षा की आवश्यकता है। अशिक्षा भी आदिवासियों के शोषण को बढ़ाती रही है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता में कुछ सुधार हुआ है। शिक्षा ने युवाओं में जागरूकता और ताकत ला दी है जो अब बदले हुए परिदृश्य की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। अनुसूचित के बीच अशांति के विभिन्न कारण

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

एतिहासिक परिद्रश्य :

जनजातियों की पहचान और विश्लेषण किया गया है। आदिवासियों में असंतोष समय और फिर से अलग राज्य के रूप में सामने आया है या विकास के बेहतर सौदे के लिए एक आंदोलन के रूप में। 3 आदिवासी वे लोग हैं जो जंगल में रहते हैं और यही मूल कारण है कि वे उनसे बहुत निकट से जुड़े हैं। वन उनके अस्तित्व का एकमात्र साधन और उनके अस्तित्व के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हैं। वे न केवल जंगल को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, बल्कि प्रति कहे जाने वाले पूरे पर्यावरण। आदिवासी वे लोग हैं जो प्रकृति में पिछड़े हुए हैं और प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए मूल तत्वों पर रहते हैं। आज भी वे प्रकाश और ऊर्जा के मूल स्रोत के रूप में सूर्य के प्रकाश हैं और वे जो अन्य प्रकाश जानते हैं, वह आग से उत्पन्न होता है। बिजली शब्द भी कई जनजातियों के लिए ज्ञात नहीं है। यही कारण है कि वे पेड़ों से लेकर नदियों तक के पर्यावरण के हर हिस्से को अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं क्योंकि वे अपनी समझ के अनुसार मानव अस्तित्व का एकमात्र साधन हैं। पर्यावरण को दिए जाने वाले महत्व की मात्रा यहां सीमित नहीं है पर्यावरण को भगवान की स्थिति के रूप में और वे पेड़ों, सूर्य नदियों, वायु और भूमि की पूजा करते हैं। वे पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी इसे मानव जाति के स्वामी के प्रति अपनी जिम्मेदारी मानते हैं

ट्राइबल एंड फॉरेस्ट से संबंधित संबंध। आदिवासी शांतिप्रिय लोग हैं। परंपरागत रूप से बस्ती या खेती के लिए कब्जे वाली भूमि के प्रति उनका लगाव बेजोड़ है। वे आम तौर पर अपने क्षेत्र पर आक्रमण का विरोध करते थे। उन्होंने समयसमय पर मनी लेंडर्स-, मिडिल मैन, कॉन्ट्रैक्टर्स, शराब विक्रेताओं, जमींदारों और सरकारी प्रशासकों, विशेष रूप से वन, व्यायाम, पुलिस और राजस्व अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अपने शोषक के खिलाफ हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की। रिकॉर्ड किए गए इतिहास, विशेष रूप से ब्रिटिश के आगमन के बाद आदिवासियों द्वारा अंग्रेजों के साथसाथ उनके अस्ति-त्व के लिए अन्य शोषकों द्वारा किए गए संघर्षों की एक श्रृंखला का उल्लेख है और उन्होंने अपने स्वयं के पारंपरिक कानूनों, कानूनी प्रणालियों और रीतिरिवाजों का पालन - किया। विभिन्न मुद्दों को किसी तरह से आदिवासी संस्कृति, योजना और आदिवासी क्षेत्रों की स्वशासन के विकास से संबंधित वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास योजनाओं के साथ समस्या यह है कि वे शायद ही कभी आदिवासियों की मौजूदा संस्कृति और अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

हैं। इन कार्यक्रमों को लागू करने का तर्क इस विश्वास से बनाया गया है कि आदिवासी पिछड़े और असहाय हैं और उन्हें बाहरी लोगों को अपने अभिभावक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है

उद्देश्य:

भारतीय स्वतंत्रता और इसे 'कल्याणकारी राज्य' घोषित करने के बाद, भूख, गरीबी, बीमारी और अशिक्षा से पीड़ित गरीब जनता के विकास को सुनिश्चित करना हमारे योजनाकारों का बाध्य कर्तव्य बन गया। आदिवासियों सहित समुदाय के कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए संविधान में विशेष प्रावधान शामिल थे। आदिवासियों को केवल जंगलों और पहाड़ियों में सभ्यता से दूर रहने वाले लोगों के रूप में माना जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, अंग्रेजों द्वारा पीछा की जाने वाली नीति-नीति को अब और जारी नहीं रखा जा सकता था। आदिवासियों को भी समाज के अनुरूप आने का अधिकार था और इसके लिए उनके और बाकी लोगों के बीच की खाई को पाटना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद, वन विभाग ने वनों को विकसित करने का एकाधिकार ले लिया और आदिवासी अपने वनों और पहाड़ियों में विशेष रूप से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रख्यापन के बाद विदेशी हो गए।

वन अधिनियम, ब्रिटिश औपनिवेशिक दिनों का उत्पाद होने के नाते, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक हितों के बजाय उस समय के औपनिवेशिक और सामंती समाज के शोषणकारी इरादों को दर्शाता है। राजस्व-उन्मुख नीति के आधार पर, इसका मुख्य उद्देश्य वन उपज में लेनदेन को विनियमित करना और इमारती लकड़ी पर कर्तव्यों का लाभ उठाकर सरकारी खजाने को बढ़ाना था। अधिनियम में आरक्षण और आरक्षण की घटनाओं के लिए प्रक्रियाओं का भी प्रावधान है। (क) उत्तराधिकार को छोड़कर कोई भी अधिकार आरक्षित वन में या अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है; या (बी) सरकार के साथ दिए गए अनुदान या अनुबंध के तहत; या (ग) पहले से मौजूद अधिकारों वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। मसौदा अधिसूचना जारी होते ही अधिकार खो गए थे। किसी भी व्यक्ति को जंगलों में आग लगाने, शिकार करने, अत्याचार करने, उत्खनन करने, मछली पकड़ने और जाल लगाने के लिए निषिद्ध कृत्यों में लिप्त होने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरी ओर राज्य सरकार किसी आरक्षित वन में अपने किसी भी अधिकार को ग्राम समुदाय को सौंप सकती है और आगे नियम 9 बना सकती है

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

महत्व:

राज्यों के हिस्सों पर। वन भूमि और निवास स्थान पर उनकी गैर-मान्यता एक ऐतिहासिक अन्याय था। 2007 का वन अधिकार कानून 10 का उद्देश्य इस अन्याय को दूर करना है। आदिवासी लोगों और अन्य वनवासियों को कुछ अधिकारों 12 और कर्तव्यों के साथ समाप्त करना, कानून जनजातीय लोगों और जंगल के संबंधों को पहचानने का प्रयास करता है। वन अधिकार अधिनियम पर छाया डालने वाली अशिष्टताएँ हैं जो आदिवासी गाँवों को धर्मांतरित करने की क्षमता रखती हैं। आदिवासियों को उनके मूल निवास स्थान पर बहाल करने के उद्देश्य से निजीकरण की इस तरह की एक गुप्त प्रक्रिया कानून के बहुत उद्देश्य को हरा देगी। एक अन्य भविष्यवाणी परिणामी है जो गंभीर वन्यजीवों के आवास के प्रावधान से बहती है। महत्वपूर्ण वन्यजीवों में वन अधिकारों को बाद में संशोधित या पुनर्जीवित किया जा सकता है जब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिकारियों को संतुष्ट किया जाता है कि वन अधिकारों के धारकों की उपस्थिति की गतिविधियां या प्रभाव अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बनता है और उक्त प्रजातियों और अस्तित्व के लिए खतरा है। उनके निवास स्थान ।१ परिणामस्वरूप, वन क्षेत्र जहां आदिवासी क्षेत्र है जहां आदिवासी लोगों को निर्वाह की तलाश में स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता है और आजीविका काफी हद तक कम हो गई है। अधिनियम के बहुत उद्देश्य को प्रभावित करने के रूप में महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास के प्रेरण की आलोचना की जा सकती है। आदिवासियों को दुश्मनों के रूप में मानने वाले वन अधिकारों से संबंधित कोई कानून, और न ही दोस्तों के रूप में, वन निवास स्थान केवल घुसपैठियों को मुखौटा बनाने में मदद करेगा, और वन समुदायों को बलि का बकरा माना जाएगा। इस तथ्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा माना और स्वीकार किया गया है जब उसने सुझाव दिया कि बाघ आरक्षित राज्यों को क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ स्थानीय वन आवास जनजातियों की भर्ती करनी चाहिए। यह उन लोगों के बीच भेद करने के लिए आवश्यक है जो जीवित और आजीविका के लिए जंगलों में हैं, और जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए और लाभ कमाने के लिए हैं। Letter यह पत्र श्रेणी है जिसे वनों तक पहुँचने से रोकने की आवश्यकता है। यही असली लड़ाई है ।१४

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

परिणाम:

ट्राइब्स और उनके प्रदर्शन के संरक्षण के लिए प्रस्तावों का अभाव। वन अधिनियम के फ्रैमर्स की मूल चिंता उस समय के शाही और सामंती हितों की रक्षा करना था। मामलों के विश्लेषण से पता चलता है कि अदालतों ने तंत्र में बदलते समय की जरूरतों को कैसे अनुरूप किया। सत्तर के दशक में, अदालतों ने पर्यावरण क्षरण की कीमत पर अन्य सामाजिक मांगों के दावों को सही ठहराया। अस्सी के दशक में, पर्यावरण संरक्षण के महत्व को पहचाना जा रहा था। नब्बे के दशक में, वे आगे बढ़े और मौजूदा कानून में पर्यावरणीय मूल्यों को पढ़ा। इक्कीसवीं सदी में, अदालतों ने प्राकृतिक पुनर्जनन और महत्वाकांक्षी पुनर्वास योजनाओं के लिए reg शुद्ध वर्तमान मूल्य 'और purpose विशेष उद्देश्य वाहन' को शामिल करते हुए नई रणनीतियों की वकालत की है जब वन गैर-वानिकी विकास उद्देश्यों के लिए है। 15

संवैधानिक सुरक्षा उपाय और अन्य संबंधित कानून।

1) क्षेत्र अवलोकन के अनुसार, इच्छित उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के रास्ते में एक प्रमुख बाधा राज्य स्तर पर प्रासंगिक कानूनों और नियमों में संशोधन करने में देरी थी।

2) राजस्व, वन, सिंचाई, खानों, मत्स्य पालन, उत्पाद शुल्क के विभागों को शायद अभी तक नए प्रावधानों के अनुसार विभागीय अधिकारियों की बदली हुई भूमिकाओं के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है।

3) आदिवासी क्षेत्रों के निर्वाचित व्यक्तियों के प्रशिक्षण को भी आदिवासियों के बीच भागीदारी और सशक्तिकरण के संबंध में ऐसे प्रावधानों के बारे में आदिवासियों में जागरूकता पैदा करने के लिए नहीं रखा गया था।

4) इन सबसे ऊपर, PESA16, 1996 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य स्तर पर राजनीतिक समर्थन और जड़ता की कमी प्रतीत होती है।

५) राज्य सरकार ने १९९९ का एक अधिनियम भी पारित किया, शायद कानूनी बाध्यता के कारण, जिसके अनुसार १९९ was तक PESA को राज्यों द्वारा अधिनियमित किया जाना था, जिसे दो वर्ष के लिए प्रदर्शित किया गया था और संबंधित नियमों में संशोधन के बाद चार साल से अधिक की देरी हुई है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

संविधान अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। इन्हें मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, (1) संरक्षण और (2) विकास। अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण उनके विकास के लिए बहुत आवश्यक है।

राज्य के क्षेत्रों के। इस अनुच्छेद के अनुसरण में, अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है। प्रावधान के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक विशिष्ट योजनाओं के खिलाफ अनुदान दिया जाना है और केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। विशिष्ट योजनाओं के बिना अनुदान जारी किया जाता है।

अनुच्छेद 339 (2) अभी भी आगे बढ़ता है और राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक होने के निर्देश में निर्दिष्ट योजनाओं के ड्राइंग और निष्पादन के रूप में एक राज्य को निर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय कार्यकारी को अधिकार देता है। राज्य सरकारों द्वारा खराब प्रदर्शन के बावजूद इन प्रावधानों में निहित शक्तियों का अब तक उपयोग नहीं किया गया है और कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 244 के मद्देनजर, यदि जनजातीय संस्कृति को संरक्षित किया जाना है, तो पारंपरिक कानूनों और रीति-रिवाजों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

(१) जो आदिवासियों के आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं और उन्हें सशक्त बनाते हैं,

(२) जो भूमि के प्रगतिशील कानून की भावना के विरुद्ध हैं, और अंत में

(३) जो आदिवासियों को विकास कार्यक्रमों के लाभ में बाधा डालते हैं।

परंपराओं को प्रगति के साथ मेल खाना चाहिए। सीमा शुल्क को प्रगतिशील कानून और संविधान की भावना के साथ फिट होना चाहिए। महिलाओं की समानता का सम्मान किया जाना चाहिए। ग्राम सभा को सशक्त किया जाना चाहिए, और आदिवासियों के अलग-थलग पड़े संसाधनों को बहाल किया जाना चाहिए। तथाकथित तकनीकी अपराधों के कारण उन्हें पुलिस अभियोजन या अदालतों के उत्पीड़न से बचाया जाना चाहिए। जनजाति संस्कृति के संरक्षण के साथ मिलकर आर्थिक प्रगति का आदर्श वाक्य होना चाहिए।

पोस्बल समस्या समाधान मोड:

किसी को यह समझना होगा कि समूहों के बीच गरीब लोगों का अस्तित्व जो उन विशेषताओं की विशेषता है जो संरचनात्मक-वैधानिक या सामाजिक-विशेषाधिकार को जोड़ती हैं, असमानता और

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

उत्पीड़न से कम विशेषाधिकार प्राप्त समूहों की सुरक्षा के खिलाफ कोई तर्क नहीं है। गरीब-आदिवासी और गैर-आदिवासी की वांछित एकता के लिए-वास्तविक के लिए बहुत गुंजाइश है (जैसा कि मजबूर के विपरीत) एकता: वन भूमि और अन्य वन उपज जैसे लकड़ी और चरागाह तक पहुंच की कमी; वन अधिकारियों के साथ-साथ राजस्व और आदिवासी कल्याण अधिकारियों के भ्रष्ट और दमनकारी व्यवहार; लघु वन उपज (तेंदू पत्ता, और गोंद, उदाहरण के लिए) की खरीद के लिए कम मजदूरी का भुगतान; वन विकास निगम के डिपो में आकस्मिक श्रम के लिए कम मजदूरी का भुगतान; ये सभी सामान्य समस्याएं हैं जिन्होंने आदिवासी और गैर-आदिवासी गरीबों को एकजुट किया है

राज्य और अन्य दमनकारी ताकतों के खिलाफ सीपीआई (एमएल) समूहों के नेतृत्व में एक संयुक्त संघर्ष में अनुसूचित क्षेत्र। 37 विशेष रूप से, अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-आदिवासी जमींदारों की भूमि का विनियमन, और वन भूमि के साथ-साथ वन भूमि पर राज्य के एकाधिकार का पूरी तरह से युक्तिकरण, आदिवासियों की समस्याओं को सुलझाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और गैर-आदिवासी गरीब यह सच्चाई है कि राज्य नहीं चाहता है कि लोगों को एहसास हो और इसलिए यह आदिवासियों के हितों को 'छोटे' गैर-आदिवासी भूस्वामियों के खिलाफ खड़ा करता है ।.38 ग्रामीण क्षेत्रों में, यह वास्तव में दलित, आदिवासी और सीमांत किसान हैं जो वास्तव में वनीकरण और वन संरक्षण से लाभान्वित होंगे। जैसे, उन्हें विभिन्न प्रकार की बुनियादी दैनिक जरूरतों के ईंधन, कृषि उपकरण, आवास आदि के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, जिनके पास न तो पहुंच होती है, न ही वे केरोसिन और रसोई गैस का खर्च उठा पाएंगे। एल्यूमीनियम, सीमेंट जैसी अधिक महंगी आवास सामग्री उनकी पहुंच से बाहर है। लघु वनोपज न केवल आय का एक स्रोत हैं, बल्कि काफी हद तक उनकी स्वास्थ्य स्थिति को भी प्रभावित करते हैं। एक सहजीवी संबंध में आदिवासी अपरिवर्तनीय रूप से और जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। उनके सक्रिय सहयोग के बिना, कोई वनीकरण कार्यक्रम कभी सफल नहीं होगा ।.39 आम तौर पर यह माना जा सकता है कि यह वर्तमान विकास प्रणाली जीवन के जनजातीय तरीके से बेहतर है लेकिन इस दृष्टिकोण को चुनौती दी जा रही है। वास्तव में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो रहा है कि आधुनिक औद्योगिक विकास मॉडल पर्यावरणीय रूप से अस्थिर, आर्थिक रूप से अस्थिर और सामाजिक विघटन का कारण है। हाल के दिनों में आदिवासी आंदोलन न केवल राज्य की मांग पर केंद्रित रहे हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधन-उपयोग और जीविका के अधिकार के मुद्दों को जबरन विस्थापन के विरोध के रूप में लिया

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

है। ये नए प्रकार के आंदोलन इस अहसास का परिणाम हैं कि अकेले राज्य का लाभ प्राप्त करना, अलगाव की समस्या का कोई जवाब नहीं है, जिसकी जड़ें ब्रिटिश उद्योग के हितों के अनुसरण में अंग्रेजों द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण में हैं। नर्मदा परियोजना के खिलाफ चल रहे संघर्ष ने इस संबंध में पूरे देश की कल्पना को जन्म दिया है ।

भूमि किसान हक्का सावरक्षण समिति डांग जिले (गुजरात) के आदिवासियों के बीच उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। समिति ने वन और पुलिस विभागों द्वारा उनके दमन के खिलाफ आदिवासियों की एक रैली का आयोजन किया था। समिति की प्रमुख मांगों में काम करने का अधिकार, बेघरों के लिए उचित आश्रय और भूमि पर अधिकार शामिल है, जो सदियों से आदिवासियों ने खेती की है, और बिजली, स्कूल, परिवहन, सड़क और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी प्रावधान है। यह अफ़सोस की बात है कि अगर कुछ व्यक्ति और संगठन आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें संगठित करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा 'लोकतांत्रिक कल्याण' राज्य उन्हें गुंडों और अपराधियों के रूप में मानता है। यह केवल राज्य की मशीनरी नहीं है जो इस तरह की लोकतांत्रिक गतिविधियों को दबाने के लिए बल का उपयोग करती है। यहां तक कि प्रेस के वर्गों ने उन्हें 'अपराधियों और नक्सलियों के गिरोह' के रूप में कलंकित किया है। जब कुछ व्यक्तियों ने इस तरह की अव्यवसायिक पत्रकारिता के खिलाफ विरोध किया, तो क्षेत्रीय पत्रों में से किसी ने भी उन पत्रों की एक जोड़ी को प्रकाशित नहीं किया जिन्हें उन्हें भेजा गया था। लाइन के विकास और प्रदर्शन के बारे में जानकारी। अब वन कानून लागू होने के कारण आदिवासी अपनी ही जमीन में घुसपैठ करने लगे हैं, जो उन्हें मामूली वनोपज से कमाई करने से रोकते हैं। मैदानी इलाकों में खेतिहर मज़दूरों के रूप में आदिवासी, जो अपनी ज़मीनों और लोगों से अलग-थलग हैं, बेहाल आर्थिक हालात में जी रहे हैं। भारत के कई हिस्सों में, आदिवासी जो खेती करने वाले थे वे खेतिहर मजदूर बन गए हैं। परिणामस्वरूप, उनकी स्थिति चरमरा रही है। पुलिस, जमींदार और राजनेता लॉबी या सांठगांठ देश में कहर ढा रहे हैं। यह खेत को खा जाने वाली बाड़ की तरह है; पुलिस, जो लोगों की मदद करने वाली है, गुजरात के भरूच जिले के वालिया में ही नहीं, बल्कि देश के कई अन्य हिस्सों में आम लोगों पर आतंक फैला रही है। राज्य मशीनरी द्वारा इस तरह की बर्बरता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे और अधिक सहन नहीं किया जा सकता है भारत के विकास मॉडल को इस तरह देखा जा सकता है कि, बड़ी परियोजनाओं के कारण होने वाले

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

विस्थापन से वास्तव में समाज के कमजोर वर्गों से संसाधनों का हस्तांतरण अधिक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए होता है, जिसमें कोई संदेह नहीं है। मेगा बांध, विशेष रूप से, विकास के शिकार बनाते हैं जो मुख्य रूप से आदिवासी हैं जो कभी भी विकास के लाभ को किसी भी तरीके से साझा नहीं करते हैं। यह कहा जा सकता है कि विकास परियोजना जितनी बड़ी होगी, उस पर केंद्रीयकृत नियंत्रण उतना ही अधिक होगा। इस केंद्रीकरण में बड़े भूस्वामियों, अमीर किसानों, के पक्ष में पूर्वाग्रह है।

निष्कर्ष :-

आज के समकालीन विश्व परिदृश्य में इंजीनियर, नौकरशाह और राजनेता। इस प्रकार, कोई यह देख सकता है कि विकास परियोजनाओं ने मौजूदा सामाजिक विषमताओं को कम करने के लिए बहुत कम किया है। इसके विपरीत, उन्होंने पहले से ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली के पक्ष में सामाजिक संरचना को बढ़ा दिया है, इस प्रकार भारत के संविधान में समाजवादी ढोंगियों को हवा दे रहे हैं। 43 यहाँ उद्देश्य प्रासंगिक मामले कानूनों पर एक व्यापक नज़र रखना नहीं है, जो निश्चित रूप से गरिमापूर्ण कार्य है, लेकिन इस मामले में आदिवासी अधिकारों के संबंध में काम करने के तरीकों पर ध्यान देने योग्य प्रवृत्तियों की रूपरेखा तैयार करना है। कुछ प्रमुख अदालती फैसलों पर एक सतही नज़र से पता चलता है कि आदिवासी वन और भूमि अधिकारों को अदालतों द्वारा मौकों पर गंभीरता से लिया गया है। उदाहरण के लिए, फाटसांग गिम्बा वसावा बनाम गुजरात राज्य के मामले में, गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रियायती दरों पर आदिवासियों को बिक्री के लिए बांस के परिवहन को रोकने की वन विभाग की कार्रवाई अनुचित थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि एक बार बांस को बांस के चिप्स में बदल दिया गया था, लेकिन यह प्रकृति से उपज नहीं था और इसलिए भारतीय वन अधिनियम 192745 का उल्लंघन नहीं था। श्री मांचेगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य के दोनों और लिंगप्पा गोखना बनाम महाराष्ट्र राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी भूमि की सुरक्षा के पक्ष में फैसला सुनाया: पूर्व मामले में आदिवासी भूमि की निजी खरीद को निरस्त कर दिया और बाद में राज्य को आदिवासियों को भूमि की बहाली के उद्देश्य से कानून बनाने की अनुमति दी। और उसके बाद प्रसिद्ध समता 48 निर्णय है। एक पूर्व मामले में पी। रामी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि आदिवासी भूमि को उन लोगों को हस्तांतरित करने पर

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 1, March 2021
Impact Factor: 4.819

प्रतिबंध लगाया गया था जो आदिवासी नहीं थे, उन्हें आदिवासियों की खराब आर्थिक स्थिति दी गई थी। जब आदिवासी अधिकार (भूमि या वन अधिकारों के रूप में या अधिक व्यापक रूप से आजीविका के अधिकार) विकास चिंताओं से जूझ रहे हैं, तो ये अधिकार अक्सर सीमित या पुनर्परिभाषित होते हैं। उदाहरण के लिए, बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के संदर्भ में, न्यायालयों ने सामाजिक अधिकारों और पर्यावरण की कीमत पर विकास के विशेषाधिकार प्राप्त किए हैं। नर्मदा और टिहरी के मामले तुरंत दिमाग में आते हैं, लेकिन बिजली परियोजनाओं, खनन और औद्योगिकीकरण से संबंधित इसी तरह के अन्य मामलों की मेजबानी करते हैं। में अधिक बार नहीं

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

१- गुजरात एआईआर 1987 गुजरात 9.
२- श्री मिश्रीगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य एआईआर 1984 SC 1151.
३- लिलिंगप्पा पोचन्ना बनाम महाराष्ट्र राज्य MIR1985
4- पर्यावरण शिक्षा ,एस-व्ही अग्रवाल